Drishti IAS

# करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

## जनवरी (संग्रह)

## 2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

# अनुक्रम


**उत्तर प्रदेश** **3**

- वाराणसी में देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिये 200 करोड़ रुपए मंज़ूर 3
- कर्नाटक की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में होगा खेती का सर्वे 3
- शहरी क्षेत्रों में 3000 वर्ग मीटर भूमि होने पर ही खोल सकेंगे निजी स्कूल 4
- उत्तर प्रदेश में अब ऐप से लगेगी मनरेगा श्रमिकों की शत-प्रतिशत हाजिरी 5
- मुख्यमंत्री ने किया UPPSC की नई वेबसाइट का शुभारंभ 5
- गौशालाओं के लिये बनाया जाएगा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल 6
- बनारस देगा देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट 6
- मऊ की दाक्षायनी पांडेय के कार सुरक्षा मॉडल का धमाल 7
- उत्तर प्रदेश मे वेब सीरीज पर मिलेगी भारी सब्सिडी 7
- उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेश भर में होंगे भव्य आयोजन, हर ज़िले को मिलेगा तीन लाख का बजट 8
- भारत में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज 'गंगा विलास' 8
- प्रधानमंत्री ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज-एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया 9
- बीएचयू में देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर 10
- उत्तर प्रदेश में एससीआर बनाने पर काम शुरू 11
- अलीगढ़ को मिला ट्रांसपोर्ट नगर 12
- प्रधानमंत्री ने बस्ती ज़िले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया 12
- उत्तराखंड पेयजल निगम तैयार कर रहा वाटर ग्रिड 13
- उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू 13
- उत्तर प्रदेश सरकार देगी 11 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 14
- उत्तर प्रदेश के चार परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीप 15
- कालिंजर दुर्ग में मिली दसवीं शताब्दी की मूर्तियाँ 16
- उत्तर प्रदेश दिवस पर लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित हुए प्रदेश के प्रतिभाएँ 17
- गोरखपुर एयरपोर्ट का होगा विस्तार 18
- मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जबकि प्रदेश के अन्य सात विभूतियाँ पद्म श्री सम्मान के लिये चयनित 18
- देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश 19
- प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे अस्पताल 19
- गोरखपुर के 'पनियाला' को मिला जीआई टैग 20


**नोट :**

# उत्तर प्रदेश

## वाराणसी में देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिये 200 करोड़ रुपए मंज़ूर

### चर्चा में क्यों ?

1 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के बनारस के मंडलायुत्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि बनारस में दुनिया भर से आने वाले सैलानियों को अब भीड़भाड़ वाले इलाके कैंट स्टेशन से गौदौलिया तक के सफर के लिये रोपवे की सुविधा मिलेगी, जिसके लिये देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे को धरातल पर उतारने के लिये 200 करोड़ रुपए का बजट मंज़ूर हुआ है।

### प्रमुख बिंदु

- मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि राज्य में वाराणसी कैंट से गोदौलिया के बीच सड़क किनारे से गुजर रही जनसुविधाओं की लाइन को शिफ्ट करने के लिये बजट की पहली किस्त जनवरी के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी।
- 15 जनवरी के बाद जनसुविधाओं की लाइन को शिफ्ट करने के लिये तैयारी कराई जा रही है। रूट के लिये चिह्नित जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जनवरी महीने में ही शुरू हो जाएगी।
- उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से ज़मीन अधिग्रहण के लिये 173 करोड़ रुपए और जनसुविधाओं की लाइन को शिफ्ट करने के लिये 28 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। शासन ने इस बजट प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए पहली किस्त जारी करने की पहल भी कर दी है। बजट जारी होने के बाद कैंट से गोदौलिया के बीच सड़क के नीचे से गुजर रही पानी, बिजली सहित अन्य लाइन को शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
- ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सर्वे में जलकल, स्मार्ट सिटी, गेल, जल निगम, बीएसएनएल और बिजली विभाग के निर्माण को चिह्नित किया गया है। इसके अलावा कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौराहे तक 75 किमी लंबे रोप-वे निर्माण के लिये 1.59 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण के लिये चिह्नित है, जिसमें निजी 0.96 हेक्टेयर और सरकारी 0.63 हेक्टेयर है। सर्किट रेट से तय मुआवज़ा के आधार पर निजी ज़मीन पर 72 करोड़ रुपए और सरकारी ज़मीन पर 101 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- मंडलायुक्त ने बताया कि कैंट, भारतमाता मंदिर, बेसेंट थियेसोफिकल सोसाइटी रथयात्रा, गिरिजाघर और गोदौलिया चौराहे पर स्टेशन और 30 टॉवर बनाए जाने हैं। उन्होंने बताया कि रोपवे परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में मार्च में रोपवे का काम शुरू हो जाएगा।

## कर्नाटक की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में होगा खेती का सर्वे

### चर्चा में क्यों ?

1 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में अब कर्नाटक की तर्ज पर खेती का सर्वे किया जाएगा। अभी तक प्रदेश में अनुमान के आधार पर रबी, खरीफ व जायद की खेती के क्षेत्रफल, उत्पादन, प्राकृतिक आपदा पर हुए नुकसान संबंधी आँकड़े जुटाए जाते थे।

### प्रमुख बिंदु

- कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक चला तो एक साल बाद यह साफ-साफ पता चल सकेगा कि किस ज़िले के किस किसान के पास कितनी खेती है। रबी, खरीफ और जायद में उसने कितने रकबे में क्या बोया और कितना बोया। कितना उत्पादन हुआ। इन सबके अब सटीक आँकड़े मिलेंगे। इनका डिजिटलीकरण भी होगा।
- विदित है कि अभी तक कृषि और राजस्व विभाग द्वारा ज़िला स्तर पर अनुमान पर आधारित प्रदेश की खेतीबारी के आँकड़े जुटाए जाते हैं।

नोट :

- उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सेटेलाइट मैपिंग की तैयारी की जा रही है। सेटेलाइट से ज़िलेवार, ब्लाकवार हर गाँव में किसानों के खेतों के आकार प्रकार, फसलों की बोवाई, उत्पादन आदि की सटीक जानकारी मिल सकेगी। उसी के अनुरूप किसानों को आवश्यक खाद, रसायन आदि उपलब्ध करवाया जाएगा और फसलों के चयन के बारे में एडवाइजरी दी जाएगी।
- उन्होंने बताया कि अभी तक तो प्रदेश में खेतीबारी का सारा ब्यौरा अनुमान के आकलन पर संकलित होता है। इसमें पूरी तरह साफ-साफ यह पता नहीं चल पाता कि किस किसान ने कितने क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोयी। अतिवृष्टि, बाढ़, पाला, अग्निकांड जैसी आपदा के समय भी सही-सही जानकारी जुटाने में काफी दिक्कत पेश आती है।
- गौरतलब है कि पिछले दिनों कर्नाटक के कृषि व राजस्व विभाग के अफसरों ने अपने राज्य में लागू सेटेलाइट सर्वे के मॉडल का प्रस्तुतीकरण उत्तर प्रदेश में आकर किया। कृषि मंत्री सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी यह मॉडल पसंद आया। इसे स्वीकृत किया गया और अब इसे उत्तर प्रदेश में संचालित करने की तैयारी की जा रही है।

## शहरी क्षेत्रों में 3000 वर्ग मीटर भूमि होने पर ही खोल सकेंगे निजी स्कूल

### चर्चा में क्यों ?

2 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि राज्य बोर्ड ने शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय खोलने के लिये 3000 वर्ग मीटर ज़मीन होना जरूरी कर दिया गया है, जो कि पहले यह 650 वर्ग मीटर थी।

### प्रमुख बिंदु

- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिये प्रस्तावित नए मानकों व शर्तों को शासन ने मंजूरी दे दी है। शासन ने यह मंजूरी बोर्ड द्वारा नए नियमों को लेकर आए सुझावों व आपत्तियों का औचित्य न होने की बात कहते हुए खारिज करने के बाद दी है।
- नई शर्तों के तहत अब शहरी क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिये 3000 वर्ग मीटर ज़मीन होना जरूरी होगा, जो कि पहले 650 वर्ग मीटर ही थी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में 6000 वर्ग मीटर ज़मीन की अनिवार्यता होगी, जो कि पहले 2000 वर्ग मीटर थी।
- इसके अलावा धरोहर राशि में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है। साथ ही स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास व विभिन्न संसाधन होना भी जरूरी किया गया है।
- दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये बदलाव यानी न्यूनतम मानक राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा के लिये निर्धारित हो रहे हैं। इसीलिये वित्तविहीन विद्यालयों को मान्यता देने के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
- शासन ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सभापति व सचिव को निर्देश दिये हैं इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 की धारा-16(2) में व्यवस्था के अनुसार मानकों, शर्तों की अधिसूचना गजट में प्रकाशित की जाए।
- हाईस्कूल की नवीन मान्यता के लिये प्रमुख अनिवार्य शर्तें-
  - समिति/ट्रस्ट/कंपनी अधिनियम-2013 के अध्याय 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी (नॉट फॉर प्रॉफिट) का पंजीकृत व यथा स्थिति नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
  - प्राभूत (जमानत) कोष के रूप में पाँच लाख रुपए केवल विद्यालय के नाम जमा व निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बंधक होंगे। पहले प्राभूत कोष के लिये 15 हज़ार रुपए राशि निर्धारित थी।
  - सुरक्षित कोष के रूप में डेढ़ लाख रुपए जमा होंगे, जबकि पहले मात्र 3000 रुपए जमा करना अनिवार्य था।
  - ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर, बड़ी स्क्रीन की एलईडी टीवी की व्यवस्था स्मार्ट क्लास व कंप्यूटर कक्ष में 25 कंप्यूटर की व्यवस्था करनी होगी।
  - शहरी क्षेत्र की कुल 3000 वर्म मीटर विद्यालय भूमि में 1000 वर्ग मीटर और ग्रामीण क्षेत्र की 6000 वर्ग मीटर भूमि में 2000 वर्ग मीटर भूमि का क्रीड़ास्थल होगा।

नोट :

- क्रीड़ा स्थल में एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, खो-खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, ओपेन जिम्नेजियम व अन्य आउटडोर गेम्स के साथ इनडोर गेम्स व शारीरिक सौष्ठव की पर्याप्त व्यवस्था होगी। पहले ऐसी मान्यता की शर्त नहीं थी।
- छात्र संख्या के अनुरूप एक वर्ग मीटर की दर से प्रत्येक छात्र, छात्रा के लिये कुर्सी, मेज, डेस्क बेंच की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही प्रयोगशाला की भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। पहले की शर्त में जूनियर कक्षाओं के साथ 200 सेट सज्जा होना अनिवार्य था।
- स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि की पर्याप्त व्यवस्था, छात्र, छात्राओं व दिव्यांगजन की सुविधा के अनुसार करने की विस्तृत शर्तें होंगी। पहले सिर्फ समुचित व्यवस्था की शर्त थी।
- पुस्तकालय में वृहद पाठ्य सामग्री रखनी होगी। शिक्षण सामग्री की विस्तृत व्यवस्था करनी होगी।
- संस्था में शिक्षकों, कर्मचारियों की उपस्थिति के लिये बायोमीट्रिक मशीन, वायस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन, वाई-फाई के साथ ही विद्यालय की वेबसाइट होना जरूरी होगा।
- विद्यालय भवन सुरक्षा मानकों पर निर्मित हो और वहाँ विद्युत, सौर ऊर्जा के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग व जल-मल निकासी की व्यवस्था करनी होगी।

- नए विद्यालय की मान्यता के लिये हाईस्कूल की अनिवार्य शर्तें पूरी करने के बाद इंटरमीडिएट के संचालन के लिये कुछ अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी। इसके तहत दो लाख रुपए प्राभूत कोष व सुरक्षित कोष के लिये एक लाख रुपए अतिरिक्त जमा करने होंगे।

## उत्तर प्रदेश में अब ऐप से लगेगी मनरेगा श्रमिकों की शत-प्रतिशत हाजिरी

### चर्चा में क्यों ?

2 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि राज्य में अब मनरेगा के कामों में पारदर्शिता के लिये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप से शत-प्रतिशत हाजिरी लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

### प्रमुख बिंदु

- उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में मनरेगा के कामों में पारदर्शिता लाने के लिये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप (एनएमएमएस) के माध्यम से शत-प्रतिशत हाजिरी लगाने की व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग कर रहा है।
- इसी साल से मनरेगा श्रमिकों की शत-प्रतिशत हाजिरी इस ऐप के माध्यम से लगने लगेगी। इसके लिये ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी ज़िलाधिकारियों व ज़िला कार्यक्रम समन्वयक को दिशा-निर्देश दिये हैं।
- आयुक्त ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए लिखा है कि श्रमिकों की उपस्थिति को ऐप के माध्यम से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए और इसकी समीक्षा प्रत्येक सप्ताह विकास खंड स्तर पर की जानी चाहिये।
- उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अभियान (मनरेगा) भारत में लागू एक रोज़गार गारंटी योजना है, जिसे प्रदेश में 7 सितंबर, 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था।
- इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करके ग्रामीण परिवारों के काम करने के अधिकार की कानूनी गारंटी प्रदान करना और उनकी आजीविका को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है।

## मुख्यमंत्री ने किया UPPSC की नई वेबसाइट का शुभारंभ

### चर्चा में क्यों ?

3 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में UPPSC की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। नई वेबसाइट युवाओं के लिये उपयोगी होगी और इसके साथ ही शासन और आयोग में भी बेहतर समन्वय होगा।

### प्रमुख बिंदु

- इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बार-बार विवरण नहीं देना होगा। आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) की व्यवस्था शुरू की है, जिसके अंतर्गत ओटीआर में दर्ज डिटेल्स डिजिटल रूप में कभी भी कहीं से भी उपलब्ध होगी।

नोट :

- इसके अलावा सरकारी नौकरी के अलग-अलग नोटिफिकेशन के तहत आवेदन करने के लिये रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा तथा ओटीआर में दर्ज जानकारियाँ भर्ती संस्थानों से डिजिटली सत्यापित होगी, जिससे अभ्यर्थियों को सहूलियत मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि नियुक्तियाँ समय पर हों और ई-अधियाचन की व्यवस्था लागू की जाए। इसके जरिये शासन और आयोग में पहले से बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षकों के समयबद्ध चयन के लिये बेहद गंभीर है। इसके लिये राज्य में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक ही आयोग के जरिये बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों का चयन किया जाएगा। एकीकृत आयोग के लिये दिशा-निर्देश भी दिये गए हैं। इसके बाद अब नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा आयोजित कराएगा।

## गौशालाओं के लिये बनाया जाएगा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल

### चर्चा में क्यों ?

4 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वृहद गौ-आश्रय स्थल के संबंध में प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया और बताया कि गौशाला चलाने के लिये उसकी अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिये एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा।

### प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गौशालाओं का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाए तथा साथ ही उन्हें नेचुरल फार्मिंग, गोबर पेंट, सीएनजी और सीबीजी से जोड़ा जाए। इससे गौशालाएँ आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी और गायों के रखरखाव एवं पालन पर आने वाला खर्च खुद उठा सकेंगी।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश में दो से तीन हज़ार गोवंश धारण की क्षमता वाले आश्रय स्थलों के निर्माण को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशाला संचालन के लिये इच्छुक एनजीओ के साथ एमओयू करें और उन्हें आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराएँ।
- योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य सरकार पशु संवर्धन, संरक्षण के लिये सेवाभाव के साथ सतत् प्रयासरत है। गोवंश सहित सभी पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिये सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं तथा पात्र लोगों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित कराया जाना चाहिये।
- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही निराश्रित गौ-आश्रय स्थल, सहभागिता योजना और कुपोषित परिवारों के लिये एक गाय की योजना गौ-संरक्षण में काफी प्रभावी है। पूरे प्रदेश में इन तीनों योजनाओं को अभियान चलाकर आगे बढ़ाया जाना चाहिये।
- उन्होंने बताया कि सहभागिता योजना के तहत निराश्रित गोवंश को पालने वाले किसानों को प्रति गोवंश 900 रुपए मासिक दिये जा रहे हैं। भू-सत्यापन के बाद किसानों को उनका भुगतान किया जाए।
- दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और बेसहारा मवेशियों के नियंत्रण के लिये नस्ल सुधार योजना में तेजी लाई जानी चाहिये। इस योजना के तहत पशुपालक सरकारी पशु अस्पतालों में कृत्रिम गर्भाधान करवा कर मवेशियों की नस्ल को सुधार सकते हैं। इससे दुग्ध का उत्पादन तो बढ़ेगा साथ ही मवेशियों की नई नस्ल भी तैयार हो जाएगी।

## बनारस देगा देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट

### चर्चा में क्यों ?

4 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के बनारस नगर निगम के अधिशासी अभियंता अजय राम ने बताया कि धर्म-संस्कृति के लिये विख्यात बनारस अब देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट भी देगा। कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट बनारस के रमना में निर्माणाधीन है।

नोट :

### प्रमुख बिंदु

- अभियंता अजय राम ने बताया कि बनारस के रमना में प्लांट शुरू होने पर प्रति दिन 600 टन कचरे से 200 टन कोयले का उत्पादन हो सकेगा। कचरे से कोयला बनाने वाला यह देश का पहला प्लांट होगा, जिसका निर्माण एनटीपीसी की ओर से कराया जा रहा है। प्लांट में कचरे से कोयला बनाया जाएगा। इसका सफल परीक्षण अक्टूबर 2022 में हो चुका है।
- एनटीपीसी तय मानकों पर प्लांट की एक इकाई का तकनीकी परीक्षण कर रहा है। जून माह के अंत तक प्लांट की पहली इकाई शुरू की जाएगी। उत्पादन के बाद कोयले को आसपास के ज़िलों में संबंधित कंपनियों को बेचा जाएगा।
- वाराणसी में आम दिनों में प्रतिदिन 600 टन तथा खास मौकों पर 800 टन तक कचरा निकलता है। बड़ी ट्रकों से इसे शहर के बाहर कूड़ा निस्तारण प्लांटों तक पहुँचाया जाता है।
- उन्होंने बताया कि तीन साल के ट्रायल पर यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो अन्य प्रदेशों में भी प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट निर्माण आगामी 25 साल को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। प्लांट की क्षमता आठ सौ टन से अधिक कचरा प्रसंस्करण की होगी। प्लांट को दिसंबर 2023 तक शुरू करने का लक्ष्य है।

## मऊ की दाक्षायनी पांडेय के कार सुरक्षा मॉडल का धमाल

### चर्चा में क्यों ?

5 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में एक गरीब किसान की बेटी दाक्षायनी पांडेय ( 17 वर्ष ) का चयन उनके कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर अमेरिका में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100 फीसदी स्कॉलरशिप के साथ हुआ है। इस समय वह 12वीं की पढ़ाई कर रही है।

### प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि दम घुटने से कार में एक मासूम की मौत की घटना टेलीविज़न पर देखने के बाद व्यथित दाक्षायनी पांडेय ने कार सुरक्षा का एक ऐसा मॉडल तैयार किया, जिसे देख और सुनकर पूरी दुनिया चकित है। इस मॉडल से प्रभावित होकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें बुलावा मिला।
- दाक्षायनी पांडेय स्कॉलरशिप पर बायो इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के लिये सितंबर 2023 में अमेरिका रवाना होंगी।
- उन्होंने 'मिशन प्रोटेक्टर' कारों के लिये एक सुरक्षा सेटअप बनाया है। यह वाहन में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बढ़ने के साथ ही सक्रिय हो जाता है और कार की खिड़की को अंदर ताजा हवा की अनुमति देने के लिये रोल करता है।असल में कार अगर चल रही हो और उसके शीशे बंद हों तो उसके अंदर कार्बन डाइ ऑक्साइड गैस जमा हो जाती है। इसकी वजह से कार में बैठे लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन मिशन प्रोटेक्टर की खूबी यह है कि जैसे ही कार में कार्बन डाइ ऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी यह तुरंत अलर्ट कर देगा और अपने आप कार के शीशे नीचे हो जाएंगे।
- विदित है कि दाक्षायनी ने पहली बार अपना मॉडल आईआईटी दिल्ली में आयोजित इंडिया एट 75 नेशनल आइडियाथान-2021 में प्रदर्शित किया, जिसमें उनका मॉडल प्रथम स्थान पर रहा था। वह अपने इस 'मिशन प्रोटेक्टर'को पेटेंट कराएंगी।

## उत्तर प्रदेश मे वेब सीरीज पर मिलेगी भारी सब्सिडी

### चर्चा में क्यों ?

5 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में बॉलीवुड के फिल्म निर्देशकों और कलाकारों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि यूपी सरकार प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी और वेब फिल्मों की लागत पर 25 प्रतिशत तक की छूट की दिशा में काम करने जा रही है।

### प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे के दौरान उनकी बॉलीवुड हस्तियों के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश को 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया'के तौर पर प्रमोट किया गया।

नोट :

- इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वेब सीरीज और वेब फिल्मों के साथ ही स्टूडियो और लैब के लिये 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।
- बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को 64वें और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट'का दर्जा मिला है।
- फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सब्सिडी की बात की है, उससे नए फिल्म निर्माताओं को मदद मिलेगी।
- बैठक में अभिनेता सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि 'बॉलीवुड बायकॉट'टैग को हटाया जाए, ताकि बॉलीवुड की बिगड़ी छवि को सुधारा जा सके। उन्होंने यह संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचाने का आग्रह भी किया।

## उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेश भर में होंगे भव्य आयोजन, हर ज़िले को मिलेगा तीन लाख का बजट

### चर्चा में क्यों ?

6 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 से 26 जनवरी तक लखनऊ सहित प्रदेश के सभी ज़िलों में भव्य आयोजन किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये।

### प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव के मुताबिक राज्य स्तरीय समारोह लखनऊ के अवश शिल्प ग्राम में होगा। उन्होंने इस आयोजन में सभी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
- संस्कृति विभाग की ओर से प्रत्येक ज़िले को आयोजन के लिये 3 लाख रुपए का बजट दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग, एमएसएमई एवं स्वयं सहायता समूहों की ओर से ओडीओपी के स्टाल लगाकर उत्पादों का विक्रय एवं प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
- ज़िला स्तर पर तीन दिवसीय केंद्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। खेल विभाग की ओर से खो-खो, कबड्डी, शूटिंग बॉल, बालीबाल बाल, क्रिकेट, टेनिस, दौड़, बाधा दौड़ प्रतियोगिताएँ की जाएंगी।

## भारत में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज 'गंगा विलास'

### चर्चा में क्यों ?

8 जनवरी, 2023 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी, 2023 को वाराणसी में एमवी गंगा विलास के साथ दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ भारत के लिये रिवर क्रूज पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा।

### प्रमुख बिंदु

- यह लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3,200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा।
- एमवी गंगा विलास क्रूज को दुनिया के सामने देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिये सुसज्जित किया गया है। विश्व विरासत स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों, और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की 51 दिनों की क्रूज यात्रा की योजना बनाई गई है।
- एमवी गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व के स्थानों पर रुकने के साथ भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिये तैयार किया गया है।
- वाराणसी में प्रसिद्ध 'गंगा आरती'से, यह बौद्ध धर्म की महान श्रद्धा के स्थान सारनाथ में रुकेगा। यह मायोंग को भी कवर करेगा, जो अपनी तांत्रिक विद्या के लिये जाना जाता है और माजुली, सबसे बड़ा नदी द्वीप और असम में वैष्णव संस्कृति का केंद्र है। यात्री बिहार स्कूल ऑफ योग और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी जाएंगे, जिससे उन्हें आध्यात्मिकता व ज्ञान में समृद्ध भारतीय विरासत से रूबरू होने का मौका मिलेगा।

नोट :

- यह क्रूज रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिये प्रसिद्ध बंगाल डेल्टा की खाड़ी में सुंदरबन के जैव विविधता से भरपूर विश्व धरोहर स्थलों के साथ-साथ एक सींग वाले गैंडों के लिये प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भी गुज़रेगा।
- एमवी गंगा विलास क्रूज 62 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा है और 1.4 मीटर के ड्राफ्ट के साथ चलता है। इसमें तीन डेक हैं, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले बोर्ड पर 18 सुइट हैं, जिसमें पर्यटकों के लिये एक यादगार और शानदार अनुभव प्रदान करने के लिये सभी सुविधाएँ हैं।
- जहाज अपने मूल में स्थायी सिद्धांतों का पालन करता है, क्योंकि यह प्रदूषण मुक्त प्रणाली और शोर नियंत्रण तकनीकों से लैस है। एमवी गंगा विलास की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा का आनंद लेंगे। एमवी गंगा विलास के डिब्रूगढ़ पहुँचने की संभावित तिथि 1 मार्च, 2023 है।
- उल्लेखनीय है कि एमवी गंगा विलास क्रूज अपनी तरह की पहली क्रूज सेवा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से इस सेवा की सफलता से उद्यमियों को देश के अन्य हिस्सों में रिवर क्रूज का लाभ उठाने के लिये उत्साहित होने की संभावना है।
- वैश्विक रिवर क्रूज बाज़ार पिछले कुछ वर्षों में 5 प्रतिशत की दर से बढ़ा है और 2027 तक क्रूज बाज़ार के 37 प्रतिशत तक पहुँचने की उम्मीद है। विश्व में यूरोप रिवर क्रूज जहाजों के मामले में लगभग 60 प्रतिशत भागीदारी के साथ विकास कर रहा है।
- भारत में, कोलकाता और वाराणसी के बीच 8 नदी क्रूज जहाजों का संचालन होता है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (ब्रह्मपुत्र) पर क्रूज की आवाजाही भी संचालित होती है। देश में कई जगहों पर रिवर राफ्टिंग, कैम्पिंग, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, कयाकिंग आदि जैसी पर्यटन गतिविधियाँ संचालित हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर 10 यात्री टर्मिनलों का निर्माण किया जा रहा है जो रिवर क्रूज की संभावना को और बढ़ा देगा। वर्तमान में, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में चार नदी क्रूज जहाज काम कर रहे हैं, जबकि यह राष्ट्रीय जलमार्ग 3 (वेस्ट कोस्ट कैनाल), राष्ट्रीय जलमार्ग 8, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 87, राष्ट्रीय जलमार्ग 97, और राष्ट्रीय जलमार्ग 5 में सीमित क्षमता में काम कर रहा है।
- अब जबकि अंतर्देशीय जलमार्गों में क्षमता निर्माण के लिये पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा रहा है, अर्थव्यवस्था के लिये एक व्यवस्थित फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिंकेज के साथ नदी क्रूज, विशेष रूप से नदियों के दोनों किनारों पर विकसित होने के लिये तैयार है।

## प्रधानमंत्री ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज-एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया

### चर्चा में क्यों ?

13 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज - एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया और टेंट सिटी का उद्घाटन किया।

### प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी से डिब्रूगढ़ तक के सबसे लंबे रिवर क्रूज विश्व पर्यटन मानचित्र पर उत्तर भारत के पर्यटन स्थलों को सामने लाएगा।
- साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में समर्पित की जा रही एक हज़ार करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाएँ पूर्वी भारत में पर्यटन और रोज़गार की सभावनाओं को बढ़ावा देंगी।
- रिवर क्रूज के अनुभव पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इसमें सभी के लिये कुछ न कुछ खास है। आध्यात्मिकता में रुचि रखने वालों के लिये काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली जैसे गंतव्यों को कवर किया जाएगा।
- एक बहुराष्ट्रीय क्रूज अनुभव की तलाश करने वाले पर्यटकों को बांग्लादेश में ढाका से होकर जाने का अवसर मिलेगा तथा जो भारत की प्राकृतिक विविधता को देखना चाहते हैं उनके लिये यह सुंदरबन और असम के जंगलों से होकर गुज़रेगा।

नोट :

- प्रधानमंत्री ने कहा कि यह क्रूज 25 विभिन्न नदी धाराओं से होकर गुज़रेगा इसलिये उन लोगों के लिये इस क्रूज का विशेष महत्त्व है, जो भारत की नदी प्रणालियों को समझने में गहरी रुचि रखते हैं।
- एमवी गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करते हुए 51 दिनों में लगभग 3,200 किलोमीटर की यात्रा करके भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुँचेगा।
- एमवी गंगा विलास में सभी लक्जरी सुविधाओं के साथ तीन डेक, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 सुइट्स हैं। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक पूरी यात्रा के लिये जा रहे हैं।
- एमवी गंगा विलास क्रूज को दुनिया के सामने देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये डिजाइन किया गया है। विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों के लिये क्रूज की 51 दिनों की यात्रा की योजना बनाई गई है।
- यह यात्रा पर्यटकों को एक शानदार अनुभव देगी और भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता में शामिल होने का अवसर देगी।
- रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के प्रयास के अनुरूप, इस सेवा के लॉन्च के साथ रिवर क्रूज की विशाल अप्रयुक्त क्षमता का लाभ प्राप्त करना संभव हो जाएगा और यह भारत के लिये रिवर क्रूज टूरिज्म के एक नए युग का सूत्रपात करेगी।
- वाराणसी में टेंट सिटी क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं का दोहन करने के लिये गंगा नदी के तट पर टेंट सिटी की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना शहर के घाटों के सामने विकसित की गई है जो विशेष रूप से काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद से वाराणसी में रहने की सुविधा प्रदान करेगी और पर्यटकों की बढ़ती संख्या की ज़रूरत को पूरा करेगी।
- इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। पर्यटक आसपास के विभिन्न घाटों से नावों द्वारा टेंट सिटी पहुंचेंगे। टेंट सिटी हर साल अक्टूबर से जून तक जारी रहेगी और बारिश के मौसम में नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण तीन महीने के लिये हटा दी जाएगी।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित, हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है और बर्थ को लगभग 3000 डेडवेट टन (डीडब्ल्यूटी) तक के जहाजों को सँभालने के लिये डिजाइन किया गया है।
- प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के सैदपुर, चोचकपुर, जमानिया और बलिया ज़िले के कंसपुर में चार फ्लोटिंग कम्युनिटी जेटी का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में पटना ज़िले के दीघा, नकटा दियारा, बाढ़, पानापुर और बिहार के समस्तीपुर ज़िले के हसनपुर में पाँच सामुदायिक घाटों की आधारशिला रखी गई।
- आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और क्षेत्र में स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार के लिये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में गंगा नदी के किनारे 60 से अधिक सामुदायिक घाटों का निर्माण किया जा रहा है। छोटे किसानों, मत्स्य इकाइयों, असंगठित कृषि उत्पादक इकाइयों, बागवानों, फूलों की खेती करने वालों और गंगा नदी के भीतरी इलाकों में आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कारीगरों के लिये सरल लॉजिस्टिक समाधान प्रदान करके सामुदायिक जेटी लोगों की आजीविका में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिये समुद्री कौशल विकास केंद्र का भी उद्घाटन किया। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में समृद्ध प्रतिभा पूल को तराशने में मदद करेगा और तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक उद्योग में रोज़गार के बेहतर अवसर प्रदान करेगा।
- इनके अलावा प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल में एक जहाज मरम्मत सुविधा और एक एलिवेटेड रोड की आधारशिला भी रखी। पांडु टर्मिनल पर शिप रिपेयर सुविधा से कीमती समय की बचत होगी।

## बीएचयू में देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर

### चर्चा में क्यों ?

15 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के बनारस में बीएचयू ट्रामा सेंटर के प्रभारी प्रो. सौरभ सिंह ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीएचयू ट्रामा सेंटर में देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

नोट :

### प्रमुख बिंदु

- प्रो. सौरभ सिंह ने बताया कि बीएचयू ट्रामा सेंटर में देश का पहला एडवांस केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर खुलने से ब्रेन, स्पाइन और न्यूरो की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को अब काशी में ही विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी।
- उन्होंने बताया कि स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर में ब्रेन, स्पाइनल, न्यूरो ऑप्थलेमिक इंजरी की आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के साथ ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से इलाज की सुविधाएँ मिलेंगी। इलाज की ऐसी सुविधा अभी ऑस्ट्रेलिया में है।
- विदित है कि बीएचयू ट्रामा सेंटर में वाराणसी और आसपास के ज़िलों के साथ ही बिहार, झारखंड आदि जगहों से सड़क दुघर्टनाओं में घायल गंभीर लोग आते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं, जिनके स्पाइनल और ब्रेन में गंभीर चोटें लगी होती हैं। इलाज के बाद भी व्यक्ति सामान्य जीवन में नहीं लौट पाता है।
- डॉक्टरों के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में एडवांस केयर रिहेबिलिटेशन सेंटर के माध्यम से ऐसे मरीजों का सफल इलाज हो रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया की तरह ही बीएचयू में देश का पहला ऐसा केंद्र होगा, जहाँ इस तरह की सुविधाएँ दी जाएंगी।
- ट्रामा सेंटर में बनने वाले सेंटर में रोबोटिक सर्जरी, स्पीच थेरेपी और सर्जरी के माध्यम से मरीजों को नया जीवन देने की तैयारी है। यहाँ आधुनिक तकनीक वाली मशीनें मंगाई जाएंगी। रोबोटिक सर्जरी की मदद से सड़क दुर्घटनाओं के समय पैर और शरीर के ऐसे भागों में जहाँ नसें काम करना बंद कर देती हैं। उसे रोबोटिक तकनीक की मदद से सही कराया जाएगा।
- हेड इंजरी वाले मरीजों को सर्जरी के बाद भी सही से न चल पाने और बोल पाने की समस्या रहती है। नए सेंटर में ऐसे मरीजों के लिये ऑकुपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी की व्यवस्था की जा रही है। इससे मरीजों का इलाज आसान हो जाता है।
- रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिये कुल 200 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कराया गया है। इसमें 200 बेड का सुपर स्पेशियलिटी भवन भी बनेगा। खास बात यह है कि यहाँ इलाज के साथ पठन-पाठन, शोध और मूल्यांकन की सुविधा रहेगी। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को न्यूरो, स्पाइनल इंजरी के इलाज का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- सेंटर में ये सुविधाएँ मिलेंगी -:
  - पेड यूनिट: कॉमर्शियल स्तर से चिकित्सा सुविधा का लाभ लोग ले सकेंगे। निजी हॉस्पिटल से कम खर्च आएगा।
  - सब्सिडाइज्ड यूनिट: कम कीमत पर पात्र लोगों को चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
  - स्ट्रेटिजिक फार्मेसी यूनिट: पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फार्मेसी यूनिट का संचालन होगा।
  - स्ट्रेटिजिक एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिट: ब्रेन, स्पाइन और न्यूरो की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को अब काशी में ही विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी।

## उत्तर प्रदेश में एससीआर बनाने पर काम शुरू

### चर्चा में क्यों ?

17 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के आवास विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि राज्य में एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाने पर काम शुरू हो गया है।

### प्रमुख बिंदु

- आवास विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के गठन की दिशा में बाराबंकी में सबसे पहले विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। बाराबंकी एससीआर का हिस्सा है।
- उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर एससीआर बनाया जा रहा है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात ज़िले इसके हिस्सा होंगे।
- प्रस्ताव मिलने के बाद मुख्यमंत्री के समक्ष इसका प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि बाराबंकी ज़िला राजधानी से सटा हुआ है। इसलिये इसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से अवैध कालोनियाँ बस रही हैं। बिल्डर यहाँ औने-पौने दामों पर ज़मीन लेकर आवासीय और व्यावसायिक योजनाएँ ला रहे हैं। बाराबंकी में अभी तक विकास प्राधिकरण न होने की वजह से न तो इन कॉलोनियों का नक्शा पास कराया जा रहा है और न ही इस पर रोक लग पा रही है।

नोट :

## अलीगढ़ को मिला ट्रांसपोर्ट नगर

### चर्चा में क्यों ?

17 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के हैबिटेट सेंटर में आयोजित जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद सतीश गौतम, विधायक राजकुमार सहयोगी द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर का विधिवत् शुभारंभ किया गया।

### प्रमुख बिंदु

- अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 28 साल के लंबे इंतजार के बाद अलीगढ़ को ट्रांसपोर्ट नगर मिल पाया है।
- अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में 18 फरवरी से 17 मार्च के बीच भूखंड आवंटन के लिये पंजीकरण होगा। इसमें कुल 1803 भूखंड हैं। भूखंड के लिये 16 हज़ार रुपए प्रति वर्गमीटर जमीन की दर रखी गई है। इसमें लॉटरी सिस्टम से यहाँ ट्रांसपोर्टर ही नहीं सामान्य व्यक्ति भी जमीन ले सकेगा।
- ट्रांसपोर्ट नगर में 608 भूखंड 200 वर्गमीटर, 439 भूखंड 72 वर्गमीटर, 204 भूखंड 162 वर्गमीटर, 231 भूखंड 375 वर्गमीटर के हैं। पहले चरण में ट्रांसपोर्टर, ट्रक ऑपरेटर्स, मिस्त्री दुकान, स्पेयर पार्ट्स, गोदाम, ढ़ाबा, रेस्तराँ, होटल, गेस्ट हाउस के लिये दिये जाएंगे।
- ट्रांसपोर्ट नगर में कार्यालय, फायर, पार्क, सीएनजी पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिये चार्जिंग प्वाइंट, सामुदायिक शौचालयों की सुविधाएँ होंगी।

## प्रधानमंत्री ने बस्ती ज़िले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया

### चर्चा में क्यों ?

18 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस खेल महाकुंभ के दौरान कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि जैसे इनडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेलों में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। इनके अतिरिक्त, निबंध लेखन, पेंटिंग, रंगोली बनाने जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।
- गौरतलब है कि खेल महाकुंभ का पहला चरण 10 से 16 दिसंबर, 2022 तक आयोजित किया गया था और खेल महाकुंभ का दूसरा चरण 18 से 28 जनवरी, 2023 तक निर्धारित है।
- इस सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती ज़िले के सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 से किया जा रहा है। खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो ज़िला बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच प्रदान करता है और उन्हें खेल को करियर विकल्प के रूप में लेने के लिये प्रेरित करता है। यह क्षेत्र के युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आत्मविश्वास और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाने का भी प्रयास करता है।
- प्रधानमंत्री ने खेल महाकुंभ की व्यापकता की सराहना करते हुए आशा व्य क्त की है कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम से खेलों में भारत की पारंपरिक विशेषज्ञता को एक नया आयाम मिलेगा। करीब 200 सांसद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह के खेल महाकुंभ का आयोजन कर चुके हैं।
- प्रधानमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि इन खेलों के माध्यम से प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत आगे के प्रशिक्षण के लिये चुना जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40,000 एथलीट खेल महाकुंभ में भाग ले रहे हैं।
- प्रधानमंत्री ने बताया कि खेलो इंडिया के माध्यम से 2500 एथलीटों को प्रति माह 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के तहत करीब 500 ओलंपिक संभावित खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कुछ खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए तक की सहायता मिली है।

नोट :

- देश भर में एक हज़ार से अधिक खेलो इंडिया ज़िला केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं, जिनमें से 750 से अधिक केंद्र पूरे हो चुके हैं। देश भर के सभी खेल के मैदानों की जियो टैगिंग भी की जा रही है, ताकि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग लेने में कोई दिक्कत न हो।
- उन्होंने बताया कि सरकार ने पूर्वोत्तर के युवाओं के लिये मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया है और मेरठ, (उत्तर प्रदेश) में भी एक अन्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है।

## उत्तराखंड पेयजल निगम तैयार कर रहा वाटर ग्रिड

### चर्चा में क्यों ?

19 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के पेयजल सचिव नितेश झा ने बताया कि उत्तराखंड पेयजल निगम प्रदेश के शहरों में 24 घंटे पानी की सुचारू आपूर्ति के लिये पावर ग्रिड की तरह वाटर ग्रिड बनने जा रही है। यह ग्रिड बिल्कुल पावर ग्रिड की तरह होगी, जिससे सभी पानी की लाइनें जुड़ी होंगी।

### प्रमुख बिंदु

- पेयजल सचिव नितेश झा ने बताया कि वाटर ग्रिड बनाने के लिये पेयजल निगम इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे फरवरी माह में एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि एडीबी से प्रोजेक्ट को फंड मिल सके।
- ज्ञातव्य है कि प्रदेश में अभी तक किसी मोहल्ले या क्षेत्र विशेष में ट्यूबवेल की मोटर फूँकने पर कई दिन तक पानी की किल्लत रहती है। लोग टैंकरों से पानी मंगाते हैं। कई इलाके ऐसे हैं, जहाँ गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। कई जगहों पर सर्दियों में भी पानी की परेशानी रहती है।
- इन सभी दिक्कतों के समाधान के लिये पेयजल विभाग वाटर ग्रिड तैयार कर रहा है। इस ग्रिड से सभी शहरों की पेयजल लाइनें आपस में जोड़ी जाएंगी। जहाँ भी पानी की किल्लत होगी, वहाँ ग्रिड से पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। पेयजल लाइनों को आपस में जोड़ने का यह काम जरा चुनौतीपूर्ण है।
- ऐसे काम करेगी ग्रिड-
  - जैसे पावर ग्रिड में कई बार किसी क्षेत्र विशेष में बिजली की समस्या होने पर दूसरी जगह से बिजली उपलब्ध करा दी जाती है, वैसे ही वाटर ग्रिड भी काम करेगी।
  - अगर किसी शहर के किसी क्षेत्र विशेष में पानी की कमी होगी तो ग्रिड के माध्यम से वहाँ तत्काल पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। हर मोहल्ले की मुख्य पेयजल लाइनें इस ग्रिड से जोड़ी जाएंगी।
- उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में वाटर ग्रिड स्थापित की जा रही है। यह ग्रिड पूरे साल पेयजल, औद्योगिक और कृषि उद्देश्यों के लिये पानी उपलब्ध कराने के लिये बनाई जा रही है।
- मराठवाड़ा में आठ ज़िले आते हैं। इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। इस वजह से हर साल यहाँ पानी की किल्लत पैदा हो जाती है। गुजरात में भी जलापूर्ति के लिये वाटर ग्रिड बनाने काम किया जा चुका है।
- कई इलाकों में किसी कारण विशेष से जलापूर्ति बाधित न हो, इसके लिये वाटर ग्रिड बनाने पर काम किया जा रहा है। इससे 24 घंटे पानी की उपलब्धता संभव हो सकेगी।

## उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू

### चर्चा में क्यों ?

20 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बंगलुरु में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक -2023 में बताया कि उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की फसलों की खेती को बढ़ावा देते हुए आच्छादन बढ़ाने, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि कर मूल्य संवर्द्धन और विपणन की व्यवस्था की जा रही है।

नोट :

### प्रमुख बिंदु

- राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि मोटे अनाज की फसलों की खेती को बढ़ावा देते हुए आच्छादन बढ़ाने, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि कर मूल्य संवर्द्धन और विपणन की व्यवस्था के अंतर्गत 55 मोटा अनाज प्रसंस्करण और पैकिंग के केंद्र स्थापित किये जाएंगे, जिससे 72 हज़ार 500 किसान प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे।
- इसके अलावा जन सामान्य को आहार में मोटे अनाज को शामिल करने के लिये भी जागरूक किया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि मोटा अनाज भारत का पारंपरिक भोजन है। मोटा अनाज ग्लूटेन मुक्त, उच्च प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा से भरपूर होता है।
- विदित है कि उत्तर प्रदेश में 2020-21 में 83 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया गया था। इसमें 9.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में केवल बाजरा बोया गया था। शेष क्षेत्रफल में ज्वार, कोदो, सावां, मड़वा तथा काकून बोया गया था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश मोटा अनाज के लिये अपार संभावनाओं से भरा हुआ है।
- कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोटे अनाज को लेकर पूरे देश में जागरूकता बढ़ी है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ही वर्ष 2018 में मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया तथा इसके उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास लगातार किये जा रहे हैं।
- इसके अलावा केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 में खाद्य पोषण और सुरक्षा के लिये मिलेट्स को खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत न्यूट्री अनाज उपमिशन के रूप में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाने लगा है तथा उसके मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है।

## उत्तर प्रदेश सरकार देगी 11 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान

### चर्चा में क्यों ?

22 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश शासन के अनुसचिव रघुनाथ प्रसाद वर्मा ने बताया कि प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के यशभारती सम्मान की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी देश-विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को 'उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान' से नवाज़ेगी।

### प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश शासन के अनुसचिव रघुनाथ प्रसाद वर्मा की ओर से इस नई सम्मान योजना के लिये 50 लाख रुपए की धनराशि की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
- इस योजना के तहत चार विभूतियों को क्रमश: 11-11 लाख रुपए की राशि के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार यश भारती पुरस्कार को दो साल पहले ही बंद कर चुकी है। यश भारती सम्मान के तहत 11 लाख रुपए ऐसी हस्तियों को दिये जाते थे, जिन्होंने देश-विदेश में राज्य का नाम रोशन किया हो। इसकी जगह अब संस्कृति मंत्रलय ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरूआत की है।
- उन्होंने बताया कि आगामी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री इस नई पुरस्कार योजना की शुरुआत करते हुए चार विभूतियों को सम्मानित कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना के लिये जारी शासनादेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश के ऐसे ख्यातिलब्ध महानुभावों, जिन्होंने विभिन्न विधाओं और कार्यक्षेत्रों जैसे- कला एवं संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाजसेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, ग्राम्य विकास आदि में व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित किए। इसके अलावा इन नए उत्कृष्ट आयामों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल किया गया हो, उन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से अलंकृत किया जाएगा।
- इस सम्मान के लिये नामित व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। विभिन्न विधाओं, कार्यक्षेत्र के ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त महानुभाव, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और दीर्घ साधना के आधार पर श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की हो, जिन्होंने देश-विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया हो।

नोट :

- राज्य सरकार या केंद्र सरकार से पूर्व में किसी अन्य राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार या सम्मान प्राप्त विभूतियों को इस सम्मान योजना की पात्रता परिधि में नहीं रखा जाएगा।
- योजना के तहत हर साल संस्कृति निदेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर डीएम से नामांकन प्राप्त किये जाएंगे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों व विधाओं से संबंधित नामांकन संबंधित विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव के माध्यम से और मान्यता प्राप्त संगीत, नृत्य, नाटक, फिल्म व मीडिया की शिक्षण तथा प्रदर्शन संस्थानों व अन्य स्रोतों से प्राप्त नामांकन भी प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर चयन समिति गठित कर नाम प्रस्तावित कर सकता है।
- इन श्रेणियों में से चयनित होंगी विभूतियाँ-
  - शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत (गायन, वादन, नृत्य)
  - ललित कला, नाट्य विधा, फिल्म व मीडिया
  - समाज सेवा, युवा कल्याण, समाज कल्याण, महिला एवं दिव्यांगजन कल्याण
  - कृषि, उद्यान, दुग्ध विकास, गौसेवा, पशुपालन, वन एवं वन्यजीव तथा पर्यावरण संरक्षण
  - उद्यमिता, कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्वावलंबन
  - अन्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल आदि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाली विभूतियों, जिन्हें स्क्रीनिंग कमेटी सुपात्र समझे।

## उत्तर प्रदेश के चार परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीप

### चर्चा में क्यों ?

23 जनवरी, 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती (पराक्रम दिवस) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया। इस सूची में उत्तर प्रदेश के चार परमवीम चक्र विजेता शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के चार परमवीर चक्र विजेताओं में से तीन- कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार वीर अब्दुल हमीद, नायक जदुनाथ सिंह, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडेय को मरणोपरांत और मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को जीवित रहते ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
- उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के धरमपुर गाँव में जन्में वीर अब्दुल हमीद 27 दिसंबर, 1954 को 21 वर्ष की आयु में ग्रेनेडियर्स इंफैंट्री रेजीमेंट में भर्ती हुए थे। पाकिस्तान के साथ लड़ाई में उन्होंने अपनी तोपयुक्त जीप से पाकिस्तान के तीन पैंटन टैंक ध्वस्त किये थे। प्रतिक्रियास्वरूप पाकिस्तानी सेना ने उन पर एक साथ हमला बोला था। इसी हमले में वह शहीद हो गए थे। भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनके असाधारण योगदान को देखते हुए उन्हें 10 सितंबर, 1965 को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
- लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का जन्म सीतापुर ज़िले के रूधा गाँव में 25 जून, 1975 को हुआ था। वह एनडीए से भारतीय सेना में चुने गए। उन्हें 11 गोरखा राइफल्स रेजीमेंट की पहली बटालियन में बतौर कमीशंड ऑफिसर शामिल किया गया था। 1999 के कारगिल युद्ध में उन्होंने दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त किया था। इसी दौरान सिर में गोली लगने के कारण मात्र 24 वर्ष की आयु में वह शहीद हो गए थे। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उनके साहस और नेतृत्व के लिये मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
- उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले की कलान तहसील के गाँव खजुरी के निवासी जदुनाथ सिंह को 1941 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल किया गया था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा में जापान के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया। भारतीय सेना की राजपूत रेजीमेंट में रहते हुए उन्होंने 1947 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया। 6 फरवरी 1948 को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में जदुनाथ सिंह ने अकेले ही कबाइली भेष में आए पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसी लड़ाई के बीच एक गोली उनके सिर में आकर लगी थी, जिससे वह वीरगति को प्राप्त हुए थे। नायक जदुनाथ सिंह को भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
- मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई, 1980 को बुलंदशहर के औरंगाबाद गाँव में हुआ था। 1996 में 16 साल की आयु में वह 18 ग्रेनेडिएर्स में भर्ती हुए थे। 1999 में कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जा करने में उन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया

नोट :

था। कैप्टन योगेंद्र यादव ने कई गोलियाँ लगने के बावजूद घायल हालत में टाइगर हिल की तीन चौकियों पर कब्जा किया था और वहां तिरंगा लहराया था। इस संघर्षपूर्ण मिशन को पूरा करने वाले योगेंद्र यादव को मात्र 19 साल की उम्र में भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र सम्मान दिया गया था।

- उल्लेखनीय है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को सम्मान प्रदान करने के लिये वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने रॉस द्वीप समूह का नाम बदलकर 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप'रख दिया था। नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर 'शहीद द्वीप'और 'स्वराज द्वीप'कर दिया गया था।
- देश के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान देने के उद्देश्य से इस द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है।
- इन द्वीपों का नाम जिन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा वे हैं - मेजर सोमनाथ शर्मा; सूबेदार और मानद कैप्टन (तत्कालीन लांस नायक) करम सिंह, एम.एम; सेकेंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे; नायक जदुनाथ सिंह; कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह; कैप्टन जीएस सलारिया; लेफ्टिनेंट कर्नल (तत्कालीन मेजर) धन सिंह थापा; सूबेदार जोगिंदर सिंह; मेजर शैतान सिंह; सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद; लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुर्जोरजी तारापोर; लांस नायक अल्बर्ट एक्का; मेजर होशियार सिंह; सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल; फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों; मेजर रामास्वामी परमेश्वरन; नायब सूबेदार बाना सिंह; कैप्टन विक्रम बत्रा; लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे; सूबेदार मेजर (तत्कालीन राइफलमैन) संजय कुमार; और सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त (मानद कैप्टन) ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।

## कालिंजर दुर्ग में मिली दसवीं शताब्दी की मूर्तियाँ

### चर्चा में क्यों ?

23 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश सामाजिक संस्था कालिंजर शोध संस्थान के निदेशक अरविंद छिरौलिया ने बताया कि राज्य के बांदा ज़िले में ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी समेत अनेक देवी-देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ मलबे से निकली हैं।

### प्रमुख बिंदु

- अरविंद छिरौलिया ने बताया कि कालिंजर दुर्ग में कई छोटे-बड़े सरोवर और तालाब हैं। उन्हीं में से एक कोटि तीर्थ सरोवर है, जहाँ मूर्तियाँ व पत्थरों पर बनीं कलाकृतियाँ मिली हैं, जो नवीं और दसवीं शताब्दी की हैं।
- उन्होंने बताया कि कुछ पत्थरों पर देवी-देवताओं की नक्काशी है। इसमें भगवान विष्णु, गणेश, लक्ष्मी जी, पार्वती जी की प्रसन्न मुद्रा वाली भी मूर्तियाँ हैं। शिवलिंग को छोड़कर अधिकतर मूर्तियाँ खंडित हैं।
- कालिंजर दुर्ग के इतिहास के जानकार समाजसेवी विवेक शुक्ला ने बताया कि 1986 में दुर्ग तक जाने के लिये रोड बनाई जा रही थी। तब भी खोदाई के दौरान इसी तरह से मूर्तियाँ निकली थीं। उन्हें पुरातत्त्व विभाग ने संरक्षित कर राजा अमान सिंह महल में रखवा दिया था।
- दुर्ग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि तब 282 केएफ नंबर से 305 तक की मूर्तियाँ और तोप के गोले निकले थे। उनको पुरातत्त्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया था। इसके अलावा 1960 में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने कालिंजर दुर्ग को अपने संरक्षण में लिया था।
- ज्ञातव्य है कि कालिंजर काफी प्राचीन दुर्ग है, जहाँ गुप्त काल से लेकर बुंदेलों तक का शासन रहा है। यहाँ पर पूर्व में भी निर्माण कार्य के दौरान इस तरह की मूर्तियाँ मिलती रही हैं।
- विदित है कि तीर्थ सरोवर कालिंजर दुर्ग का सबसे सुंदर और पौराणिक स्थल है। पूरा दुर्ग भारतीय पुरातत्त्व विभाग के अधीन है। सरोवर की दीवार से मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ सहेजकर इसका निर्माण दोबारा कराया जा रहा है। सरोवर के चारों तरफ की प्राचीन दीवारों पर देवी-देवताओं की मूर्तियाँ व कलाकृतियाँ हैं।
- कालिंजर इतिहास से जुड़े अरविंद छिरौलिहा ने बताया कि भारत पर राज करने वाला छठवाँ शासक औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य उसका शासन रहा, इसे मूर्ति भंजक कहा जाता था। वह हिन्दू धर्म की मूर्तियों को खंडित करवा देते थे।

नोट :

- वर्ष 1812 से 1947 के बीच ब्रिटिश शासन के समय पर हिन्दू धर्म से जुड़ी स्मृतियों को भी नष्ट करने का काम किया जाता था। कोर्ट तीर्थ सरोवर काफी प्राचीन है, लेकिन इसके चारों तरफ की दीवारें अंग्रेजों द्वारा बनाई गईं थीं। तब दीवार के पीछे यह मूर्तियाँ भी दबा दी गईं थीं, जिससे कि सनातन धर्म और हिन्दू धर्म जागृत न हो सके।
- कालिंजर दुर्ग नीलकंठ मंदिर के राजपुरोहित पंडित शंकर प्रताप मिश्रा ने बताया कि कोटि तीर्थ सरोवर में सभी तीर्थों का जल मिला है। ऐसे में इस सरोवर के जल से यहीं पर विराजमान भगवान नीलकंठ का जलाभिषेक करने से एक हज़ार गायों के दान का पुण्य मिलता है। खास तौर से कार्तिक पूर्णिमा पर जलाभिषेक अधिक फलदायी माना जाता है।

## उत्तर प्रदेश दिवस पर लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित हुए प्रदेश के प्रतिभाएँ

### चर्चा में क्यों ?

24 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा खेल की उपलब्धियों के लिये प्रदेश की प्रतिभाओं को लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

### प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, कॉमनवेल्थ पुरस्कार विजेताओं को सम्मान एवं 16 लोगों को विवेकानंद यूथ अवार्ड दिये गए।
- माटी कला बोर्ड खादी ग्रामोद्योग के तहत छह लोगों को भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हाथों पुरस्कार दिया गया।
- रानी लक्ष्मीबाई/लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कुल 12 प्रतिभाओं में लखनऊ के हैंडबाल खिलाड़ी मोहित यादव और कानपुर नगर की ज्योति शुक्ला तथा लखनऊ के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई शामिल हैं।
- इसके अलावा पिछले साल ब्रिटेन के बर्मिंघम में 28 जुलाई से आठ अगस्त तक आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले और प्रतिभाग करने वाले 14 खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया। इनमें कामनथवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 75 लाख, काँस्य पदक विजेता को 50 लाख और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को पांच लाख रुपए की राशि के चेक दिये गए।
- व्यक्तिगत श्रेणी में 10 युवाओं और 6 मंगल दल श्रेणी (महिला-पुरुष) को मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया। इनमें लखनऊ के अमरेंद्र कुमार व रोहित कुमार कश्यप भी शामिल हैं।
- सामूहिक श्रेणी के अंतर्गत युवक मंगल दल (पुरुष) प्रथम-द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के लिये अमेठी के भादर विकास खंड के सोनारी ग्राम पंचायत के युवक मंगल दल (अध्यक्ष श्रवण कुमार), अमरोहा के गंगेश्वरी विकास खंड के तरौली ग्राम पंचायत के युवक मंगल दल (अध्यक्ष नितेश नागर), भदोही के डीघ विकास खंड के बिहरोजपुर ग्राम पंचायत के युवक मंगल दल ( अध्यक्ष जीत नारायण) का चयन किया गया था ।
- महिला मंगल दल में अमरोहा के धनौरा विकास खंड के नीलीखेड़ी ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल (अध्यक्ष कोमल), अमेठी के मुसाफिरखाना विकास खंड के सादीपुर ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल (अध्यक्ष पल्लवी), रायबरेली के डीह विकास खंड के टेकारी सहन ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल (अध्यक्ष आशा) का चयन किया गया था।

सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों की सूची -

- रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार
  - वर्ष 2021 - सामान्य वर्ग: ज्योति शुक्ला (कानपुर, हैंडबाल), नेहा कश्यप (मेरठ, वुशू)
  - वर्ष 2020-21 - वेटरन वर्ग: तरुणा शर्मा (मेरठ, जूडो)
  - वर्ष 2021-22 - सामान्य वर्ग: मनीषा भाटी (गौतमबुद्धनगर, वुशु)
- लक्ष्मण पुरस्कार
  - वर्ष 2020-21 - सामान्य वर्ग: मोहित यादव (लखनऊ)
  - वर्ष 2020-21 - वेटरन वर्ग: राहुल सिंह (वाराणसी, हाकी), जनार्दन सिंह (गाजीपुर, कुश्ती )
  - वर्ष 2021-22 - वेटरन वर्ग: मो. आरिफ (गोरखपुर, हाकी), राधेश्याम सिंह (आजमगढ़, एथलेटिक्स)
  - वर्ष 2021-22 - दिव्यांगजन वर्ग: सुहास एलवाई (पैरा बैडमिंटन, लखनऊ), विवेक चिकारा (मेरठ, तीरंदाजी), दीपेंद्र सिंह (संभल शूटिंग)।

नोट :

## गोरखपुर एयरपोर्ट का होगा विस्तार

### चर्चा में क्यों ?

24 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के ज़िलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार को रक्षा मंत्रालय ने मंज़ूरी दे दी है, जिसके लिये मंत्रालय ने एयरपोर्ट हेतु 14 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही 76.66 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिया है।

### प्रमुख बिंदु

- गोरखपुर के ज़िलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि एयरपोर्ट के विस्तार से पार्किंग वे दो की जगह 10 हो जाएंगे। वहीं वाहनों की पार्किंग भी एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही होने लगेगी। वर्तमान में गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, प्रयागराज के लिये रोज़ाना 10 उड़ानें उपलब्ध हैं।
- एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद चेन्नई, बेंगलुरु, वाराणसी समेत कई और महत्त्वपूर्ण शहरों के लिये उड़ानें शुरू हो जाएंगी।
- विदित है कि गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन परिसर में स्थित 14 एकड़ भूमि, जो गोरखपुर एयरपोर्ट को सौंपी गई है, वह राजस्व दस्तावेज़ में रक्षा मंत्रालय के नाम पर अंकित है। इसी ज़मीन के हस्तांतरण के लिये ज़िला प्रशासन ने राज्य सरकार का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा था।
- गोरखपुर एयरपोर्ट के निदेशक अनिल कुमार द्विवेदी ने बताया कि एयरपोर्ट के विस्तार हो जाने से विमानों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही यात्रियों की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इसके विस्तार से कई और शहरों के लिये सीधी उड़ान सेवाएँ शुरू हो जाएंगी।

## मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जबकि प्रदेश के अन्य सात विभूतियाँ पद्म श्री सम्मान के लिये चयनित

### चर्चा में क्यों ?

25 जनवरी, 2023 को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2023 के लिये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों 'पद्म पुरस्कारों'की घोषणा की। इनमें उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जबकि प्रदेश के अन्य सात विभूतियों को पद्म श्री अवार्ड के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2023 के लिये राष्ट्रपति ने तीन द्वय मामलों (एक द्वय मामले में, पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है) सहित 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है।
- सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएँ हैं और विदेशियों/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं।
- समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को नागरिक मामले में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार लिये चुना गया है।
- पद्म श्री पुरस्कार के लिये चयनित उत्तर प्रदेश के सात विभूतियों में राधा चरण गुप्ता, दिलशाद हुसैन, अरविंद कुमार, मनोरंजन साहू, रित्विक सान्याल, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और उमा शंकर पांडे शामिल हैं।
- राधा चरण गुप्ता और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, दिलशाद हुसैन और रित्विक सान्याल को कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, मनोरंजन साहू को चिकित्सा के क्षेत्र में तथा उमा शंकर पांडे को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये पद्म श्री अवार्ड हेतु चुना गया है।
- गौरतलब है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार शामिल हैं। पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के रूप में प्रदान किये जाते हैं। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है।
- यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में दिये जाते हैं।

नोट :

- असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म विभूषण', उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म भूषण'और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म श्री'से सम्मानित किया जाता है।
- ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोहों में प्रदान किये जाते हैं जो आमतौर पर हर साल मार्च/अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किये जाते हैं।

## देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश

### चर्चा में क्यों ?

27 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि महज़ आठ साल में 47 करोड़ नए बिजली कनेक्शन देने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक विद्युत उपभोक्ताओं वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु हैं।

### प्रमुख बिंदु

- विदित है कि उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 74 करोड़, महाराष्ट्र में करीब 2.40 करोड़ और तमिलनाडु में करीब 2.20 करोड़ है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल उपभोक्ताओं की संख्या करीब तीन करोड़ बताई जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश से 23 से 25 लाख कम है।
- पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि बीते आठ साल में प्रदेश के 8 करोड़ से अधिक परिवार ढिबरी और लालटेन युग से बाहर निकल आए हैं। इस अवधि में प्रदेश में बिजली के नए कनेक्शन का रिकॉर्ड भी बना है।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2014 तक राज्य में कुल करीब 42 करोड़ उपभोक्ता थे, वहीं वर्ष 2014 से नवंबर 2022 के बीच राज्य में 1.8 करोड़ नए उपभोक्ताओं के घरों में बिजली पहुँची। बिजली के साथ ही इन परिवारों में पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी पहुँच गए।
- एम. देवराज ने बताया कि राज्य के लोगों के रहन-सहन में सुधार को ऐसे भी समझा जा सकता है कि वर्ष 2014 में बिजली की अधिकतम मांग 12327 मेगावाट रिकॉर्ड की गई थी, जो 2022 में 26589 मेगावाट पहुँच गई। बिजली के कनेक्शन दोगुने से अधिक हुए तो खपत भी उसी गति से बढ़ गई।
- प्रदेश सरकार ने हर घर को बिजली कनेक्शन देने का अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 2017 से अब तक एक करोड़ 47 लाख 90 हज़ार नए कनेक्शन दिये जा चुके हैं। इसमें बड़ी भूमिका 'सौभाग्य योजना'के तहत कनेक्शन देने की रही।
- उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने बताया कि वर्ष 2017 से 2021 के बीच 'सौभाग्य योजना'के तहत प्रदेश में 18 लाख कनेक्शन दिये गए थे। इस योजना में अधिक कनेक्शन देने पर भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत भी किया था।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश में 'रिवैम्प्ड योजना'के तहत बिजली व्यवस्था को और बेहतर किया जा रहा है। बिजली उत्पादन से लेकर वितरण तक कई योजनाओं पर काम शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध बिजली मिलेगी।

## प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे अस्पताल

### चर्चा में क्यों ?

29 जनवरी, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की तर्ज़ पर अब 50 बेड और 200 बेड के अस्पताल भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर खोले जा सकेंगे। इसके लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने नीति जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- इन अस्पतालों में मरीज़ों को नि:शुल्क इलाज मिलेगा। मरीज़ पर होने वाला खर्च सरकार उठाएगी। इन अस्पतालों में आयुष्मान सहित अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा।
- राज्य सरकार की ओर से 16 असेवित ज़िलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। अब अस्पताल खोलने के लिये भी नीति तैयार की गई है। इसके लिये सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच एमओयू होंगे।
- सरकार निजी क्षेत्र के लोगों को अस्पताल के क्षेत्र में निवेश के लिये आकर्षित कर रही है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में ज़्यादा-से-ज़्यादा नए अस्पताल खोलकर मरीज़ों को सस्ती दर पर इलाज उपलब्ध कराया जाए।

नोट :

- पीपीपी मॉडल पर खुलने वाले 50 बेड के अस्पताल के लिये सरकार वाइबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत ज़मीन उपलब्ध कराएगी। कॉर्पोरेट कंपनी अस्पताल बनाएगी। सरकार और कंपनी के बीच उपचार का मूल्य तय हो जाएगा। करीब 30 साल बाद यह अस्पताल जस-का-तस सरकार को लौटा दिया जाएगा।
- इसमें दूसरा विकल्प यह दिया गया है कि निजी क्षेत्र की कंपनी खुद ज़मीन खरीदेगी और अस्पताल बनवाएगी। उसका रखरखाव सहित अन्य सुविधाएँ वही देगी। फिर अस्पताल सरकार को वापस कर देगी। इसके लिये सरकार और कंपनी के बीच एमओयू होगा। उसमें नियम एवं शर्तें तय की जाएंगी।
- वहीं, 200 बेड का अस्पताल बनाने के लिये निजी क्षेत्र की कंपनी ज़मीन खरीदकर अस्पताल बनवाएगी और उसका रखरखाव करेगी। निर्धारित समय बाद अस्पताल उत्तर प्रदेश सरकार को लौटा देगी।

## गोरखपुर के 'पनियाला' को मिला जीआई टैग

### चर्चा में क्यों?

29 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की हाईपावर कमेटी ने जिन 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग के लिये अनुमति दी है, उनमें पनियाला भी शामिल है।

### प्रमुख बिंदु

- जीआई टैग की अनुमति मिलने से गोरखपुर के लच्छीपुर और आस-पास के गाँवों में पैदा होने वाले पनियाला का स्वाद अब देश-दुनिया तक पहुँचेगा। नष्ट होते जा रहे पनियाला के पेड़ संरक्षित किये जाएंगे, पनियाला के बगीचे तैयार होंगे और उसके फल के खट्टे-मीठे स्वाद का लोग आनंद उठाएंगे।
- ज्ञातव्य है कि पनियाला आकार और रंग में जामुन से मिलता-जुलता है तथा इसका स्वाद खट्टा-मीठा है।
- उत्तर प्रदेश स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड की ई-पत्रिका के मुताबिक स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह कहाँ का पेड़ हैं। संभावना इस बात की ज़रूर है कि यह मूलत: उत्तर प्रदेश में ही पाया जाने वाला फल है। पनियाला की वास्तविक उपज भले ही कहीं हो, लेकिन गोरखपुर महानगर के उत्तरी इलाके में स्थित लच्छीपुर से लेकर नकहा रेलवे स्टेशन के बीच इसके कई बागीचे थे। पहले लच्छीपुर की पहचान ही पनियाला थी। लंबे समय तक इस गाँव के लोगों की आय का ज़रिया पनियाला और अमरूद के फल थे।
- उल्लेखनीय है कि पनियाला 60 से 90 रुपए किलो तक बिक जाता है। कभी-कभी 100-150 रुपए किलो तक भी बिकता है। एक पेड़ से 4000 रुपए की आय हो जाती है।
- वर्ष 2011 से 2018 के बीच पं. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग में हुए कई शोध में यह बात सामने आई कि पनियाला गुणों की खान है। शोध के अनुसार इसके पत्ते, छाल, जड़ों एवं फलों में बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है। पेट से जुड़े रोगों में पनियाला काफी लाभकारी होता है। दाँतों और मसूढ़ों में दर्द, इनसे खून आने, कफ, निमोनिया और खराश आदि के इलाज़ में भी इसका प्रयोग होता रहा है। इसे संरक्षित कर लंबे समय तक रखा भी जाता है।
- विदित है कि पं. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के शिक्षक प्रो. वी.एन. पांडेय के निर्देशन में उनकी शोध छात्रा निहारिका पांडेय द्विवेदी ने भी पनियाला पर अपना शोध पूरा किया था। वर्ष 2015 में निहारिका का शोध सामने आया, जिसे विशेषज्ञों ने खूब सराहा। पनियाला में सेहत के लिहाज से कई फायदेमंद तत्त्व पाए गए।

नोट :